दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायससाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 17 नवम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 50

महत्वपूर्ण एवं खास

मिड-डे मील बनाते समय ब्वॉयलर में विस्फोट, चार की मौत

मोतिहारी (आरएनएस)। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र में आज सुबह खाना बनाने के ब्वॉयलर फटने से कई लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की संख्या का सही-सही पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि शवों के चीथड़े उड़ गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में चार लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को उपचार के लिए पीएचसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा सुगौली रेलवे गुमटी के निकट स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा था तभी अचानक ब्वॉयलर में रिसाव के कारण आग लग गयी। इसके बाद सिलेंडर धमाके के साथ फट गया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

युवा मामले और खेल मंत्रालय, एनएसएस रोकेंगे बाल यौन उत्पीड़न

नईदिल्ली (आरएनएस)। युवा मामले और खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) निदेशालय ने स्टॉप चाइल्ड सैक्सुअल एब्यूज पहल के तहत रक्षिन अभियान के जरिये बाल यौन उत्पीड़न रोकने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत तीन घंटे की प्रो-बोनो कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में युवा मामले और खेल मंत्रालय, एनएसएस का सहयोग एक संगठन साक्षी करेगा। इस योजना को मूर्त रुप देने के लिए 120 घंटे की राष्ट्रीय सेवा योजना पाठ्यक्रम में द रक्षिन प्रोजेक्ट की एक कार्यशाला को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। एनएसएस और कार्यशाला के दौरान लोगों को कानून और समान संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा और क्रिएटिव एक्सप्रेशन, काउंसलिंग, कानूनी सहायता और सस्टेंड एंगेजमेंट के जरिए हर समय उनकी सहायता के लिए तैयार रहेगा।

श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू

कोलंबो। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए शनिवार सुबह मतदान शुरू हो गया। देश में मतदान के लिए लगभग 12,845 केंद्र बनाये गये हैं जिन में 1.59 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान सुबह सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे समाप्त हो जायेगा। राष्ट्रपति पद के लिए 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में पूर्व रक्षा मंत्री एवं श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार गोतबाया राजपक्षे और कैबिनेट मंत्री एवं सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल पार्टी के उम्मीदवार साजित प्रेमदासा के बीच कड़ा मुकाबला है। यह चुनाव देश के इतिहास में सबसे महंगा भी होगा। चुनाव आयोग ने अनुमान लगाया है कि इसकी लागत 7.5 अरब श्रीलंकाई रुपये (4.1 करोड़ डॉलर) है। बड़े मतपत्र, बड़ी मतपेटियों, चुनाव ड्यूटी पर सैकड़ों अतिरिक्त कर्मचारी और पानी, टेलीफोन और बिजली के बिल जैसे अतिरिक्त खर्च ऐसे कारक हैं, जिन्होंने चुनावी बिल को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 60,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की है।

राजमार्ग अवरुद्ध करने पर जेयूआई-एफ के नेताओं, कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज

इस्लामाबाद। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक राजमार्ग को अवरुद्ध करने के लिए मामला दर्ज किया गया है, जो कराची को बलूचिस्तान से जोड़ता है। मौजूदा सरकार के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना समाप्त करने के बाद पार्टी ने इसके खिलाफ दूसरे चरण का अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। डॉन न्यूज के मुताबिक, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जेयूआई-एफ के नेताओं और समर्थकों सहित 250 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार को उन्होंने अचानक राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वाहनों के बीच टक्कर हुई और उनमें से कुछ को नुकसान पहुंचा है।

शेषन की स्मृति में चुनाव अध्ययन हेतु अंतर-विषयी दृष्टिकोण पर एक विजिटिंग चेयर स्थापित करेगा चुनाव आयोग

» पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी विजिटिंग चेयर के संरक्षक होंगे

अहमदाबाद (आरएनएस)। नये भारत के साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन के विशेष लगाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) के सेंटर फॉर कॉरिकुलम डेवलपमेंट में चुनावी अध्ययन के अंतर-विषयी दृष्टिकोण पर एक विजिटिंग चेयर स्थापित करने और उसके वित्त पोषण का निर्णय लिया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी इस चेयर के संरक्षक होंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शनिवार को अहमदाबाद के निरमा विश्वविद्यालय के विधि संस्थान में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। इस अवसर पर निरमा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. के. करसनभाई पटेल, चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा, कुलपति डॉ. अनूप सिंह, विधि संकाय संस्थान की निदेशक डॉ. पूर्वी पोखरियाल और बड़ी संख्या में छात्रा उपस्थित थे। अरोड़ा को विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री एवं न्यायविद नानी पालखीवाला की स्मृति में आयोजित लॉ कॉन्क्लेव के अवसर पर आमंत्रित किया गया था।

इस अवसर पर बोलते हुए अरोड़ा ने कहा, 'भारत की चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में संभावना, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा में टी एन शेषन के स्थायी योगदान ने उनके नाम को दुनिया भर में सर्वोत्तम चुनावी प्रथाओं का पर्याय बना दिया है। उनकी स्मृति में भारतीय चुनाव आयोग इस चेयर की स्थापना करेगा। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि अगले शैक्षणिक सत्र अगस्त-सितंबर 2020 के दौरान यह चेयर पूरी तरह काम करना शुरू कर दे।' महासचिव उमेश सिन्हा, आईआईआईडीईएम के महानिदेशक धर्मेंद्र शर्मा और ईसीआई की निदेशक मोना श्रीनिवास इस चेयर की स्थापना के विस्तृत तौर-तरीके निर्धारित करेंगे और उसे 15 मार्च, 2020 तक आयोग के सामने पेश किया जाएगा। विजिटिंग चेयर कार्यक्रम के तहत चुनाव अध्ययन से संबंधित क्षेत्रों में दमदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले युवा शिक्षाविदों को लक्षित किया जाएगा। उम्मीद की गई है कि चेयर चुनाव अध्ययन के विशिष्ट पहलुओं पर एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी भी आयोजित करेगा।

गोवा के समीप मिग लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित

पणजी (आरएनएस)। शनिवार को दोपहर के समय एक मिग-29के दो सीटों वाला लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण के लिए गोवा के डाबोलिम नौसेना एयर बेस से उड़ान उड़ान भरा लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद पक्षियों के झुंड से उसका सामना हो गया।

पायलट ने देखा कि बायां इंजन बाहर निकल गया था और दायें इंजन में आग लग गई थी। मानक संचालन प्रक्रियाओं के जरिये विमान को ठीक करने की कोशिश की गई लेकिन आपात स्थिति के कारण उसमें सफलता नहीं मिली। पायलटों ने बुद्धिमानी दिखाई और वे विमान को घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर जाकर सुरक्षित बाहर गये। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए नौसेना द्वारा एक जांच समिति स्थापित की गई है। पायलट कैप्टन एम. शोखंद और लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक यादव सुरक्षित हैं और उन्हें बचा लिया गया है। जमीन पर भी किसी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई है।

एमनेस्टी के दफ्तरों पर सीबीआई की रेड

» विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी

नईदिल्ली (आरएनएस)। एमनेस्टी के बेंगलुरु और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर सीबीआई की विभिन्न टीमों ने आज छापेमारी की है। ये छापेमारी इंटरनेशनल ग्रुप पर नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी फंडिंग हासिल करने के मामले की जांच के लिए की गई। एमनेस्टी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के लिए काम करती है। सीबीआई की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए, समूह ने कहा कि उसे देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बोलने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान जारी कर कहा है कि वह भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह पालन करती है, उसने यह भी आरोप लगायाकि यह कार्रवाई उसे परेशान करने के लिए की गई है। एननेस्टी इंटरनैशनल इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि संस्था के बेंगलुरु स्थित ऑफिस में सीबीआई की करीब 6 लोगों की टीम सुबह साढ़े 8 बजे पहुंची और यह छापेमारी शाम तक जारी रही। अक्टूबर 2018 यानी पूरे सालभर पहले प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ छापेमारी कर जांच की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों का उल्लंघन किया और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआई) नाम से एक नई कंपनी के खाते में 36 करोड़ रुपये लिए।

नकली इनवॉइस जारी करने के रैकेट का हुआ खुलासा

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय जीएसटी दिल्ली-पश्चिम आयुक्तालय ने मेसर्स रॉयल सेल्स इंडिया और 27 अन्य मुखौटा कंपनियों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली इनवॉइस जारी करने के रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को नई दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच में पाया गया कि

आरोपी गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की सुविधा हासिल करने के लिए 28 फर्जी कंपनियों का संचालन कर रहे थे। इस प्रकार वे सरकारी खजाने को चूना लगा रहे थे। प्रथम दृष्टिया पाया गया कि 900 करोड़ रुपये के इनवॉइस के जरिये लगभग 108 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट की धोखाधड़ी की गई है। जांच के परिणाम आने पर ही शुल्क की अंतिम रकम का पता चल पायेगा।

इन कंपनियों के सामानों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं की खोज के आधार पर पता चला कि इस गोरखधंधे में 28 फर्जी कंपनियां संलिप्त हैं। मामूली भुगतान लोगों के केवाईसी दस्तावेज के उपयोग से दिल्ली में इन सभी कंपनियों का फर्जी जीएसटी पंजीकरण हासिल किया गया और बिना समान के इनवॉइस एवं ई-बिल जारी किये गये। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इन कंपनियों की आवक और आपूर्ति में कोई तालमेल में नहीं था। इन कंपनियों ने बिना समान के इनवॉइस जारी कर वस्तुओं की बिक्री अथवा बिक्री के प्रभाव का सहारा लिया और चेक द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बाद दूसरे पक्ष को नकद में रकम लौटाई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत देनदारी से बचाया जा सके और कुछ मामलों में जीएसटी रिफंड आदि का फायदा उठाया जा सके।

पासवान ने जारी की भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार जल गुणवत्ता रिपोर्ट

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय खाद्य एंव उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में उपलब्ध जल की गुणवत्ता पर रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट हर घर में 2024 तक नलों के जरिए लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जल जीवन अभियान के अनुरूप जारी की गई है। खाद्य एंव उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो के माध्म से दिल्ली तथा राज्यों की राजधानियों में नल के जरिए आपूर्ति किए जाने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता जांच करायी और जांच के नतीजों के आधार पर राज्यों,स्मार्ट शहरों और जिलों को रैंकिंग दी गई।

पहले पहले चरण में, दिल्ली के विभिन्न स्थानों से पीने के पानी के नमूने लिए गए थे और दूसरे चरण में 20 राज्यों की राजधानियों से नमूने इकठ्ठा किए गए थे। इन नमूनों को भारतीय मानक 10500: 2012 (बीसीआई द्वारा निर्धारित पेयजल के लिए विशिष्टता) के अनुसार परीक्षण के लिए भेजा गया। जाचं के पहले चरण में इन नमूनों का विभिन्न मापदंडों जैसे कि ऑर्गनोलेप्टिक और फिजिकल टेस्ट, रासायनिक परीक्षण, विषाक्त पदार्थ और बैक्टीरिया आदि की मौजूदगी के हिसाब से परीक्षण किया गया। मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित एक या अधिक मापदंडों को पूरा करने के मामले में बहुत सारे नमूने विफल रहे है।

इनमें से दिल्ली कि विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए पानी के ग्यारह नमूने कई निर्धारित मानदंडों में से खरे नहीं उतर पाए। हालांकि मुबंई से एकत्र किए गए 10 नमूने सभी मानदंडों पर खरे पाए गए। हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर, अमरावती और शिमला के पानी के एक या उससे अधिक नमूने मानदंडों पर सही नहीं पाए गए। तेहर राज्यों की राजधानियों जैसे चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, पटना, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलूरु, गांधीनगर, लखनऊ, जम्मू, जयपुर, देहरादून, चेन्नई और कोलकाता से लिए गए पानी के नमूनों में से कोई भी निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए गए।

टैक्स ट्रिब्यूनल ने खारिज की यंग इंडिया की अर्जी

» राहुल को लगा बड़ा झटका

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल ने बड़ा झटका दिया है. इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें यंग इंडिया को चैरिटेबल संस्था बनाने के लिए कहा गया था. इस अर्जी को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये एक व्यवसायिक संस्थान है. गांधी परिवार ने दावा किया था कि यंग इंडियन चैरिटेबल संस्था है और उसे टैक्स में छूट मिलनी चाहिए. रिपोर्ट के मुताबिक इसका अर्थ ये हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के इन्कम टैक्स का केस फिर खुल सकता है.

सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल के सामने आया कि कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन को लोन दिया था. जिससे उसने असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (छ्रु) के साथ मिलकर बिजनेस किया था. रिपोर्ट के मुताबिक अब कांग्रेस को इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है, क्योंकि उसने इन कंपनियों को मदद करके नियमों का उल्लंघन किया है.

'सुशासन संकल्पः जम्मू घोषणा' प्रस्ताव पारित

» 19 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया

नईदिल्ली (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में केन्द्र के समान सुशासन के बेहतर तौर तरीके अमल में लाने के विषय पर कल जम्मू शुरु हुआ दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. जितेन्द्र सिंह ने किया था। उद्घाटन सत्र में जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल जी. सी. मुरमु, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी. वी. आर सुब्रह्मण्यम,डीओपीटी तथा डीएआरपीजी सचिव डा.सी चंद्रमौली,डीएआरपीजी के अपर सचिव वी श्रीनिवास और कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे।

आज जम्मू में आयोजित समान सत्र में पिछले दो दिनों से जारी गहन विचार विमर्श के बाद एकमत से सुशासन संकल्प का प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि भारत सरकार तथा इसमें भाग लेने वाले केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रशासन के स्तर पर निम्न लिखित बातों का ध्यान रखेंगे।

उपराज्यपाल के सलाहकार के. के. शर्मा, डीएआरपीजी के अपर सचिव वी . श्रीनिवास एआर तथा जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसाल, जीएडी के सचिव फारूख अहमद लोन, डीएआरपीजी की संयुक्त सचिव सुजया दूबे तथा कई अन्य अधिकरी सम्मेलन के समापन सत्र में मौजूद थे।

दो दिवसीय सम्मेलन में डिजिटल गवर्नेंस से लेकर क्षमता निर्माण तथा कार्मिक प्रशासन जैसे विषयों पर कई सत्र आयोजित किए गए।

परिवार और व्यापार साथ चलाते है सोनिया-राहुल : रविशंकर

» यंग इंडिया केवल 50 लाख में ही 2000 करोड़ से अधिक मूल्य वाली संपत्तियों की मालिक बन गये

नई दिल्ली (आरएनएस)। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एक और हमला करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा यंग इंडियन लिमिटेड को गैर-लाभकारी संस्था बताने के गांधी परिवार के दावे को खारिज किये जाने पर सोनिया गाँधी व राहल गाँधी पर जम कर हमला बोला। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के सत्ता से जाने के लगभग साढ़े पांच वर्षों बाद हमें यह लगा था कि अब कांग्रेस के एक परिवार के घोटालों की दास्ताँ बाहर आने कम हो जायेंगे लेकिन ये है कि रुकता ही नहीं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला कांग्रेस के पारिवारिक घोटाले का एक और उदाहरण है कि परिवार और कारोबार साथ-साथ चलता है और इसे ऊपर से राजनीति का कलेवर दे दिया जाता है। ट्रिब्यूनल के फैसले से इसकी आधिकारिक और वैधानिक पुष्टि हुई है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरूआत की थी,जिसे एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड

(एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 2008 में 90 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ अखबार को बंद कर दिया गया। एजेएल को बचाने के प्रयास में कांग्रेस पार्टी ने कंपनी को 2010 तक कुछ वर्षों के लिए बगैर किसी जमानत के ऋणमुक्त ब्याज दिया। 23 नवंबर, 2010 को यंग इंडियन लिमिटेड नामक एक नई कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फनार्डीस और हुआ तो हुआ वाले सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया। दिसंबर 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड के नाम 90 करोड़ रुपये कर्ज के स्थानांतरण के एवज में एजेएल ने अपने सारे शेयर वाईआईएल को देने का फैसला किया। यंग इंडियन ने इस अधिग्रहण के लिए केवल 50 लाख रुपये का भुगतान किया। कर्ज में डूबी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास अनुमानतः 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की परिसंपत्तियां थी।